बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 49 ● नई दिल्ली ● शनिवार 29 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

राजनाथ सिंह का बयानः भारत का रक्षा इकोसिस्टम नवाचार का केंद्र, बाहरी निर्भरता को करेंगे खत्म

नई दिल्ली । केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक स्थिर भारत, एक स्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, केंद्र एक रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है जो नवाचार को प्रोत्साहित करता है, उद्योग को समर्थन देता है और बाहरी निर्भरता को कम करता है। उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में चाणक्य रक्षा संवाद को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भारत शक्ति, सुरक्षा और विकास के पथ पर आगे बढ़ता है, तो विश्व को अनेक प्रकार से लाभ होता है। एक स्थिर भारत, एक स्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अनेक देशों के लिए समावेशी, पारदर्शी और सुरक्षित शासन का एक आदर्श प्रस्तुत करता है।

मानसिकता दर्शाती है, महिला कर्मियों से मासिक धर्म के सबूत मांगने के मामले में केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सफाईकर्मियों से यह साबित करने के लिए उनके निजी अंगों की तस्वीरें मांगी गईं कि उनका मासिक धर्म (पीरियड) चल रहा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, कर्नाटक में मासिक धर्म के दौरान अवकाश दिया जा रहा है। इसे पढ़कर मैंने सोचा कि क्या अब अवकाश देने के लिए भी सबूत मांगा जाएगा? उन्होंने कहा कि इससे संबंधित लोगों की सोच जाहिर होती है। अगर महिला कर्मचारी किसी जरूरी काम के लिए हाजिर नहीं थीं, तो किसी और को काम पर लगाया जा सकता था। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि इस मामले में कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर आपराधिक मामला है और इस पर ध्यान देना आवश्यक है। अब इस याचिका को 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिका में केंद्र और हरियाणा सरकार से इस घटना की विस्तृत जांच कराने के निर्देश की मांग की गई है। बार निकाय ने यह भी मांग की है कि महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता

और निजता का उल्लंघन न हो, इसके लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं। पुलिस के मुताबिक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से जुड़े तीन लोगों के खिलाफ 31 अक्तूबर को यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने महिला सफाई कर्मियों से उनके निजी अंगों की तस्वीरें मांगीं, ताकि यह साबित किया जा सके कि उनका मासिक धर्म चल रहा है। विश्वविद्यालय ने बयान जारी कर कहा कि उसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के जरिये संविदा पर रखे गए दो सुपरवाइजर्स को निलंबित कर दिया है और आंतरिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह घटना 26 अक्तूबर को उस समय हुई, जब कुछ घंटे पहले ही हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष विश्वविद्यालय के परिसर में आने वाले थे। तीन महिला सफाई कर्मियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायत दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों सुपरवाइजर्स ने पहले भी सफाई करने के लिए मजबूर किया, जब वे अस्वस्थ थे और फिर उनसे मासिक धर्म का सबूत मांगा। एक सफाई कर्मचारी ने कहा, हमने उन्हें बताया कि हम मासिक धर्म के कारण अस्वस्थ हैं, इसलिए तेजी से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने हमारे निजी अंगों की फोटो मांग ली। जब हमने मना किया, तो गालियां दी गईं और नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि सुपरवाइजर्स ने कहा कि वे सहायक रजिस्ट्रार श्याम सुंदर के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सुंदर ने इन आरोपों से इनकार किया है। पीजीआईएमएस थाना प्रभारी ने कहा कि प्राथमिकी में आपराधिक धमकी, यौन उत्पीड़न, महिला की मर्यादा का अपमान करने और मारपीट या बल प्रयोग से जुड़ी धाराएं शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

नेपाल की नई चाल? 100 रुपये के नोट पर भारतीय क्षेत्र! कांग्रेस ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र को नेपाल द्वारा एनपीआर 100 के लिए नया नोट जारी करने के कदम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

इस नोट में लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी के विवादित क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अद्यतन मानचित्र दिखाया गया है। एएनआई से बात करते हुए, पवन खेड़ा ने कहा कि यह बिल्कुल चौंकाने वाला है। भारत सरकार को समझदारी और सख्ती से काम लेने की जरूरत है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? नेपाल ने गुरुवार को एनपीआर 100 के लिए अपना नया नोट जारी किया, जिसमें लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी के भारतीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अद्यतन मानचित्र दिखाया गया है। यह बैंक नोट आज प्रचलन में आ गया। एक सार्वजनिक सूचना में, नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी), जो कि नेपाल का केंद्रीय बैंक है, ने कहा कि नए जारी किए गए एनपीआर 100 मूल्यवर्ग के नोट को प्रामाणिकता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए परिष्कृत सुरक्षा और पहचान तत्वों को शामिल करते हुए डिज़ाइन किया गया है। पिछले साल अक्टूबर में, एनआरबी ने एक चीनी कंपनी को नए बैंक नोटों की छपाई का काम सौंपा था। नेपाली मंत्रिमंडल ने मई 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में एनपीआर 100 मूल्यवर्ग के नोट के डिज़ाइन को मंजूरी दी थी। मुद्रण का ठेका चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया था। 20 मई, 2020 को, नेपाल ने एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को शामिल करते हुए एक नया नक्शा जारी किया। पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने नेपाल से लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी के क्षेत्रों के मुद्दे पर भारत के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करने का आह्वान किया, जिन्हें अब देश की नई मुद्रा में दर्शाया गया है। नए एनपीआर 100 बैंकनोट जारी होने के बाद एएनआई से बात करते हुए, फैबियन ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनावश्यक है। अगर नेपाल का मानना है कि भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा नेपाली क्षेत्र का हिस्सा है, तो नेपाल को भारत के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करनी चाहिए, न कि केवल अपनी मुद्रा पर एक नया नक्शा लगाना चाहिए।

प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की पैनी नज़र, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं - रोज़ उठा रहे हैं कदम

नई दिल्ली । दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले कई दिनों से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार स्थिति पर नियमित रूप से नजर रख रही है और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रोजाना उचित कदम उठा रही है। पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार स्थिति पर रोजाना नजर रख रही है और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नियमित रूप से उचित कदम उठा रही है। आज हम जो कदम उठा रहे हैं, उसके भविष्य में परिणाम मिलेंगे। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में उपचुनाव से पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में एक रोड शो किया। उन्होंने कहा कि हमें सभी 12 वार्डों में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और इसका असर 30 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को नतीजों में दिखेगा। दिल्ली की जनता फिर से भाजपा को चुनेगी। हम दिल्ली की प्रगति के लिए मिलकर काम करेंगे।

इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को शीतकालीन सत्र से पहले देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण पर संसद में बहस की मांग की। एक पोस्ट में, राहुल गांधी ने केंद्र पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वायु प्रदूषण की समस्या के लिए कोई तत्परता, योजना या जवाबदेही नहीं है। उन्होंने लिखा कि मैं जिस भी माँ से मिलता हूँ, वह मुझे एक ही बात कहती है उसका बच्चा जहरीली हवा में साँस लेते हुए बड़ा हो रहा है। वे थके हुए, डरे हुए और गुस्से में हैं। मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने घुट रहे हैं। आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार कोई तत्परता, कोई योजना, कोई जवाबदेही क्यों नहीं दिखाती? उन्होंने लिखा कि भारत को वायु प्रदूषण पर संसद में तत्काल, विस्तृत बहस और इस स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए एक सख्त, लागू करने योग्य कार्य योजना की आवश्यकता है। हमारे बच्चे स्वच्छ हवा के हकदार हैं - बहाने और ध्यान भटकाने वाले नहीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार सुबह 8 बजे शहर की वायु गुणवत्ता 384 एक्यूआई के साथ बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। शहर में 27 नवंबर को शाम 4 बजे एक्यूआई 377 दर्ज किया गया था। मामूली गिरावट के बावजूद, शहर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है।

दिल्ली-एनसीआर की जानलेवा हवाः किरण बेदी ने पीएमओ से कहा- अब तो कुछ करें, स्थिति दुखद

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के बीच, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करके क्षेत्र को प्रभावित करने वाले संकट के समाधान में सक्रिय हस्तक्षेप की मांग की। दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम के बारे में बात करते हुए, उन्होंने गुरुवार सुबह एक्स पर लिखा कि मैं इंदिरापुरम में रहती हूँ और अभी एक्यूआई 587 है। शिक्षकों के संदेश के बावजूद मैंने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा है। मैंने प्रधानाचार्य को एक सख्त पत्र लिखा है। मेरे नियंत्रण क्षेत्र में जो भी होगा, मैं वही करूँगी। और कहा, सर, कृपया सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करें।

उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए कहा कि स्थिति पीड़ादायक और निराशाजनक है। बुधवार को बेदी ने बताया कि कैसे बिगड़ते पर्यावरण ने उन्हें, जो शाम को टहलने की आदी हैं, घर के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया है। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा, क्या मैं अपने ही घर में एयर प्यूरीफायर के साथ बंदी बनकर रह सकती हूँ? उनकी यह टिप्पणी एक चर्चा में आई, जिसमें लंबे समय से चले आ रहे प्रदूषण आपातकाल से जुड़े राजनीतिक तर्कों पर भी चर्चा हुई। विपक्ष का रुख सामने आते ही - अब जब प्रधानमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, महापौर आपके हैं, उपराज्यपाल आपके हैं - बेदी को यह समझाया गया कि भाजपा को मुद्दे उठाने से आगे बढ़कर समाधान निकालने में सक्षम होना चाहिए। इससे पहले, जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे,

तब बहस दिल्ली के अपने शासन और आस-पास के रायों की ज़िम्मेदारी से जुड़े सवालों पर केंद्रित थी, इस बात पर ज़ोर दिया गया था। बेदी ने वर्षों के अव्यवस्थित प्रबंधन का हवाला देते हुए जवाब दिया दिल्ली वास्तव में कई मायनों में, कई रूपों में नियंत्रण से बाहर थी। उन्होंने आगे कहा कि यह क्षण समन्वय का अवसर प्रदान करता है क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि राजधानी और पड़ोसी क्षेत्रों के बीच सहयोग न हो सके। उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के 24 से ज्यादा आसपास के ज़िले इस समस्या का हिस्सा हैं, और उन्होंने कहा, इसके लिए राजनीतिक रूप से मज़बूत और राजनीतिक निर्णय लेने की ज़रूरत है। उनके रुख में बदलाव -- पहले यह पूछने से कि हर बात प्रधानमंत्री के डेस्क तक क्यों पहुँचनी चाहिए, अब हस्तक्षेप का अनुरोध करने तक -- उनके अपने अनुभव से स्पष्ट था। उन्होंने कहा, यह अब एक निराशाजनक स्थिति बनती जा रही है... ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसमें डूब रही हूँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी गंभीरता कुछ साल पहले दिल्ली निवासी बनने के बाद ही महसूस की, जबकि 2017 में वह पांडिचेरी में रह रही थीं।

उन्होंने कहा, मुझे पांडिचेरी में कभी भी इस तरह का दंश महसूस नहीं हुआ... एक बाहरी व्यक्ति इस दंश को उतना महसूस नहीं कर सकता जितना मैं अब महसूस कर रही हूँ।

लोकपाल का अधिकार क्षेत्र सीमित? दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा सचिव के खिलाफ कार्यवाही की रद्द

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) में पदोन्नति में कथित अनियमितताओं के एक मामले में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भारत के लोकपाल की कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए इस साल की शुरुआत में लोकपाल द्वारा शुरू की गई जाँच को समाप्त कर दिया। सिंह और अन्य का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, अधिवक्ता वरुण सिंह, दीपिका कालिया, काजल गुप्ता, सोमेशा गुप्ता और सुदीप चंद्रा ने किया।यह मामला अंतरिम संरक्षण में था क्योंकि पूर्ववर्ती खंडपीठ ने लोकपाल के नोटिसों और आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। पिछली खंडपीठ ने कहा था, इस न्यायालय का मानना है कि इस मामले पर गहन विचार की आवश्यकता है... यह न्यायालय 6 जनवरी 2025 के विवादित आदेश, 7 जनवरी 2025 के नोटिस, 4 मार्च 2025 के आदेश और लोकपाल के समक्ष लंबित कार्यवाही के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए इच्छुक है। यह मामला 28 मार्च, 2023 को एनपीसी द्वारा दी गई पदोन्नतियों में प्रक्रियागत खामियों का आरोप लगाने वाली एक शिकायत से उत्पन्न हुआ था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, लोकपाल ने जनवरी 2025 में सिंह और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विचाराधीन पदोन्नतियाँ सिंह द्वारा 21 अप्रैल, 2023 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले हुई थीं, और इसलिए उनकी ओर से कोई दायित्व नहीं बन सकता। उन्होंने आगे तर्क दिया कि लोकपाल की कार्रवाई लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत उसके वैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे है, जो उसके अधिकार क्षेत्र को भ्रष्टाचार के आरोपों या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों तक सीमित करता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ, उस शिकायत के तहत लोकपाल के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो गई, जिससे रक्षा सचिव, जिन्होंने 1 नवंबर, 2024 को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख और रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में अपना वर्तमान पदभार ग्रहण किया था, तथा मामले में शामिल अन्य याचिकाकर्ताओं को राहत मिली।

पढ़ा-लिखा आतंकी अधिक घातक है

लालकिले के पास कार बम विस्फोट करने वाले डाक्टर उमर नबी ने एक सेल्फी खड़े करने वाले वीडियो में इसको न्यायोचित ठहराते हुए कहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग को गलत समझा जाता है कि यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। उसके अनुसार दरअसल यह शहादत का अभियान है। वीडियो में उसका कहना है कि जिहाद में ऐसी कार्यवाही न केवल जायज़ है, बल्कि सराहनीय भी है। यह वीडियो अप्रैल में बनाया गया था पर नवम्बर में अपलोड किया गया। इसके द्वारा नबी दूसरों को सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए प्रेरित नहीं, उत्तेजित भी कर रहा है कि हमारी एजेंसियां इस वीडियो के प्रभाव को रोक नहीं सकी यह बहुत बड़ी चूक साबित होगी। असदुद्दीन ओवैसी जो मॉडरेट मुसलमानों के प्रवक्ता बन रहे है, का कहना है कि इस्लाम में बेकसूरों को मारना और खुद सुसाइड करना 'हराम' है पर सुन कौन रहा है? नबी पहला सुसाइड बॉम्बर तो है नहीं। यह सारा घटनाक्रम बहुत चिन्ताजनक है कि जिन्हें व्हाइट कॉलर कहा जाता है, अर्थात् सफ़ेदपोश, भी फिदायीन बन रहे है और दूसरों को आतंकी बनने के लिए प्रेरित कर रहे है। इस सारे घटनाक्रम में जो डाक्टर पकड़े गए है उन्होंने 75-75 लाख रुपए देकर डाक्टरी की है। वह अजमल कसाब जैसे गरीब परिवारों से नहीं है, जो बेरोज़गारी से तंग आकर आतंक के रास्ते पर चल पड़ा था। यह सब तो खाते-पीते परिवारों से है जो रेडिकल अर्थात् चरमपंथी बन गए है। नबी और उसके गैंग जिसमें आधा दर्जन से अधिक डाक्टर हैं, जिनमें एक महिला डाक्टर भी है, ने सोच-समझ कर आतंक का रास्ता अपनाया है। कोई ऐसा कष्ट नहीं था जिसने उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया हो, जो डाक्टर पकड़े गए है उनमें यह भावना खाली है कि देश और दुनिया में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और बदला लेने के लिए जेहाद और हिंसा ही रास्ता है। लगभग दो दशक से हमने ऐसी बड़ी साज़िश नहीं देखी। कश्मीर में हमले होते रहे पर आतंकी पाकिस्तान से आए थे। दिल्ली में 2011 में हाईकोर्ट के बाहर हुए विस्फोट जिसमें 12 मारे गए थे, के बाद लगभग शान्ति ही रही थी। मुम्बई के हमलावर भी पाकिस्तान से आए थे पर यह गैंग तो भारतीय नागरिकों का है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवक और युवतियां रेडिकल बन रहे है और दूसरों को रेडिकल बना रहे है। तार जैश-ए-मुहम्मद से जुड़े है पर पाकिस्तान की पहलगाम जैसी सीधी दखल नहीं है। दुनिया की नज़रों से बचने के लिए उन्होंने रणनीति बदल ली है। अब उन्होंने प्रोफेशनल को अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया है। कश्मीर में पाकिस्तान के सैल है। बहुत सैल तमाम कर दिए गए पर बहुत से जिन्दा है। मौलवी इरफान अहमद वगेय जो श्रीनगर में है ने उन्हें कट्टर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। चिन्ता यह है कि और कितने हैं जो मस्जिदों और मदरसों के द्वारा नौजवानों को गलत रास्ते में जाने के लिए प्रेरित कर रहे है? पढ़े-लिखे अधिक खतरनाक है, क्योंकि वह टैक्नोलॉजी जानते है। दूसरा संदिग्ध आतंकवादी जसीर बिलाल जो पकड़ा गया है वह ड्रोन को भारी बैटरी से फिट कर राकेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। देश के कई हिस्सों से धड़पकड़ और बरामदगी बताती है कि सारे देश में अफ़रा-तफ़री फैलाने का इरादा था। दूसरी चिन्ता की बात है कि हमारी एजेंसियां इस साज़िश को पकड़ नहीं सकी। वह अभी तक कई साज़िशों को नाकाम कर चुके है। 80 के करीब आतंकी पकड़े जा चुके है, पर आतंकि सुरक्षा के क्षेत्र में आत्म संतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। यह काम कभी खत्म नहीं होता। आप को दुश्मन से एक कदम आगे रहना है। आपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के टैरर नेटवर्क पर सीधा हमला किया था। भावलपुर में जैश-ए-मुहम्मद के हैडक्वॉटर को तबाह कर दिया, जिसमें मसूद अज़हर के परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। पता था कि बदले की कार्रवाई होगी। 18 अक्तूबर को जेश के चेतावनी वाले पोस्टर कश्मीर में नौगाम की दीवारों पर लगे पाए गए। तब एक मौलवी पकड़ा गया था जिसने बताया कि दिल्ली के आसपास के छोटे शहरों में कट्टरपंथी डाक्टरों का एक गिरोह तैयार हो रहा है। पर हमारी एजेंसियां नबी तक नहीं पहुंच सकी। तीन घंटे उसकी कार संदिग्ध हालत में दिल्ली में घूमती रही। उसने तो हड़बड़ी में विस्फोट कर दिया लगता है। दूसरा बड़ा सुराग फरीदाबाद में 2900 किलो आरडीएक्स की बरामदगी थी। अगर कहीं वह इस्तेमाल हो जाता तो बड़ी तबाही होती। यह भी बड़ी असफलता है कि दिल्ली से सटे अल-फ्लाह यूनिवर्सिटी में लम्बे समय से साज़िश तैयार हो रही थी पर किसी को खबर नहीं लगी। यूनिवर्सिटी के अधिकारी या तो सोए रहे या संलिप्त थे। इन हाथों से इस यूनिवर्सिटी को निकालने की ज़रूरत है।

बड़ा सवाल तो है कि यह डाक्टर-आतंकी इतना आरडीएक्स इकट्ठा करने में कैसे सफल रहे? क्या हम इस गलतफ़हमी का शिकार थे कि कश्मीर से धारा 370 हट गई है, बहुत मात्रा में वहां सुरक्षा कर्मी तैनात है इसलिए टैरर का इकोसिस्टम कमज़ोर पड़ गया और स्थिति नियंत्रण में रहेगी? यह भी साफ़ है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से वह संदेश नहीं पहुंचा जो हम देना चाहते थे। हो सकता है कि अमेरिका से मिले समर्थन से पाकिस्तान और दुस्साहसी हो गया है। चीन साथ है ही। नई सरदर्द पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवैध शासन की यारी है। श्रीनगर स्थित कोर के कमांडर रहे रिटायर्ड जनरल सैयद अता हसनैन ने लिखा है कि कश्मीर में आतंकवाद के पदचिन्ह चाहे सिकुड़ गए हों पर इसका वैचारिक और आर्थिक तंत्र अभी भी जिन्दा है। स्पष्ट है कि कश्मीर में आतंक की जड़ें कायम हैं। इन्हें तबाह करने की ज़रूरत है क्योंकि युद्ध अभी चल रहा है, केवल युद्ध के सिपाही की शक्ल बदल गई है। दहशतगर्दों की नई जमात खड़ी हो रही है। यह सफ़ेदपोश हमारे ही स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़-लिख कर आतंकी बन रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है। इस स्थिति से निबटना बहुत बड़ी चुनौती है। जो मॉड्यूल है उन्हें सख्ती से कुचलना चाहिए पर साथ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि और इस गलत रास्ते पर न चल सकें। पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जे.एफ. रिबेरो ने लिखा है कि, आतंकवाद की जड़ें द्वेष और अविश्वास में हैं। कड़वी सच्चाई है कि मुस्लिम समुदाय में यह प्रभाव फैल रहा है कि वह दो दर्जे के नागरिक है। इस प्रभाव को मिटाने की तत्काल ज़रूरत है। मुस्लिम समुदाय के साथ सत्तापक्ष का कोई संवाद नहीं है। लव जेहाद या लैंड जेहाद या एग्ज़ाम जेहाद या लिंचिंग जैसी हरकतें बंद होनी चाहिए। मुस्लिम रेहड़ी वालों को धमकाया जाता है। बुलडोज़र केवल मुस्लिम अपराधियों के घरों पर ही क्यों चलता है? मुहम्मद इखलाख को दादरी में इस गलतफ़हमी में लिंच किया गया कि वह गो-तस्करी में संलिप्त है अब यह समाचार है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों के खिलाफ़ मामलों को वापस लेने के बारे सोच रही है। इससे मुस्लिम समुदाय को क्या संदेश जाएगा कि कानून के आगे वह बराबर नहीं है? इससे यह भावना प्रबल होती है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और कई बदला लेने को तैयार हो जाते है। सरकार को सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ़ अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। वहां असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। यह प्रभाव खतरनाक है कि उनको हाशिए पर धकेला जा रहा है। 2005 में उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने अपनी पत्नी लौरा बुश को बताया था कि भारत में 15 करोड़ मुसलमान हैं पर एक आतंकवादी नहीं है। 20 सालों में इतना परिवर्तन क्यों आ गया है कि कुछ पढ़े-लिखे खाते-पीते मुसलमान आतंकी बन रहे हैं? हम इसे केवल कानून और व्यवस्था का मामला ही नहीं कह सकते। देश में धार्मिक नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ तारा कारथा ने लिखा है, इंडिया को अंदर झांकना चाहिए। ऐसा माहौल है जिसने युवा और महत्वकांक्षी डाक्टरों को रेडिकल बना दिया है, और कई और बनने के लिए तैयार है। मीडिया का एक वर्ग भी नफ़रत को हवा देता रहता है। इन्हें हर मामला 'हिन्दू- मुसलमान' नज़र आता है। शिक्षा संस्थाओं में कट्टरवाद को रोकने का अभियान चलाए जाने चाहिए। मदरसों की तरफ़ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कश्मीर के राजनीतिक वर्ग को फिर से साथ लेना चाहिए। संविधान सब को बराबरी का जो वादा करता है उसकी भावना को समझ कर कदम उठाए जाने चाहिए।

सम्पादकीय...

बिहार में नई राजनीति की आहट

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से इतर एक नई राजनीति की आहट साफ सुनाई दे रही है। बिहार के नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवकों को नौकरी-रोजगार का फैसला हो या फिर 25 चीनी मिलें खोलने की घोषणा, साफ संकेत देते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार इस बार ठोस आर्थिक विकास के रास्ते पर बढ़ना चाहती है। मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में बिहार आर्टिफिशियल इंटेलीजैंस मिशन बनाने की भी घोषणा की गई। बिहार में टैक हब, डिफेंस कॉरिडोर, सैमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मैगा टैक और फिनटैक सिटी बनने का फैसला भी किया गया। बिहार वासी इस तरह की पहल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सरकार के इन फैसलों पर विधानसभा चुनावों की छाप साफ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एन.डी.ए. को अखिल-स्वामी जीत भले मिल गई लेकिन चुनाव अभियान के दौरान बिहार से मजदूरों के पलायन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जवाब देना एन.डी.ए. के नेताओं के लिए भारी पड़ रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं कि 'जंगल राज' के भय और लाभार्थी मतदाताओं ने एन.डी.ए. की जीत में अहम भूमिका अदा की लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को भी जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहा जो सालों से बिहार के विकास में रुकावट बने हुए हैं। सालों बाद यह पहला चुनाव था, जब जाति पर आर्थिक मुद्दे हावी रहे। चुनाव के नारे बदले-बदले दिखाई दिए और चुनावी नतीजों के साथ ही नई सरकार के लिए नया एजैंडा छोड़ गए। नई सरकार के सामने अब पलायन और रोजगार बड़े मुद्दे हैं। बदतर शिक्षा व्यवस्था और बीमार अस्पतालों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल के फैसले साफ संकेत देते हैं कि सरकार ने इन संकेतों को समझ लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाभार्थी समूह को लुभाने पर खजाना खाली कर चुकी सरकार अब अपनी नई योजनाओं के लिए पैसा कहां से जुटाएगी। बिहार के सामने फिलहाल एक ही रास्ता दिखाई देता है, केंद्र सरकार से मदद। क्या केंद्र इतनी उदारता दिखाएगा?

बदले-बदले से सरकार – आजादी के बाद से बिहार की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार समाजवादी पार्टियों के दो धड़े ही हैं जिनकी जमीन जय प्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और डा. राम मनोहर लोहिया के विचारों पर टिकी है। नब्बे के दशक के बाद दूसरदी पट्टी पर धीरे-धीरे भाजपा का भगवा रंग छा गया लेकिन बिहार में उसकी सफलता नीतीश कुमार की बैसाखी पर ही टिकी रही। कम से कम वैचारिक स्तर पर तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी के उदय ने भविष्य की राजनीति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1990 से लेकर 2025 चुनाव पूर्व की राजनीति मुख्यतः सामाजिक न्याय की दो शक्तियों में बंटी हुई थी। एक खेमा अधिक उग्र और आक्रामक था, जिसका नेतृत्व पहले लालू प्रसाद यादव ने किया और अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इस दौर में यादव जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध पिछड़े वर्ग ने अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर संसाधनों पर सवर्ण वर्चस्व को चुनौती दी। दूसरा खेमा उदार और समावेशी था, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार ने किया। नीतीश ने ही इसे अति पिछड़ा और अति दलित का नाम दिया। यह धड़ा सवर्ण को साथ लेकर चलते हुए भी सामाजिक न्याय के रास्ते पर ही आगे बढ़ा। लेकिन राज्य में औद्योगिक विकास के अभाव ने लोगों को वास्तविक सामाजिक न्याय से दूर रखा।

बिहार से दूर बिहारी – गुजरात या राजस्थान (मारवाड़) की तरह आम बिहारी खुद उद्योग-धंधा शुरू करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं रखते। उन्हें नौकरी चाहिए-सरकारी या कम से कम प्राइवेट। लेकिन अनेक बिहारियों ने राज्य के बाहर जाकर बड़े उद्योग खड़े किए। अनिल अग्रवाल बिहार के ही हैं, जिनकी वेदांता कंपनी देश और दुनिया में स्टील और खनन के क्षेत्र में अग्रणी है। उनका पूंजी निवेश ओडिशा और अन्य कई राज्यों तथा विदेश में है लेकिन बिहार में नहीं। संप्रदा सिंह की मुंबई स्थित अलकेम लैबोरेटरीज देश की शीर्ष दवा निर्माण कंपनी है। 1990 के बाद बिहार में सामाजिक न्याय आंदोलन तो तेज हुआ लेकिन उद्योगों का सर्वनाश भी इसी दौर में शुरू हुआ। उस समय देश का लगभग 36 प्रतिशत चीनी उत्पादन बिहार में होता था। 1990 के बाद करीब 15 चीनी मिलें बंद हो गईं। बिहार में पिछले 35-40 सालों में सरकारों ने उद्योग विकास पर कभी ध्यान ही नहीं दिया।

लालू बनाम नीतीश – नीतीश ने जातियों से ऊपर उठ कर महिलाओं को पिछड़ों के अलग समूह के रूप में पहचाना, जहां लालू चूक गए थे। नीतीश ने लड़कियों की शिक्षा को सर्वोपरि रखा। 2007 में स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल बांटना शुरू करके नीतीश ने महिला को राजनीतिक शक्ति बनाने की पहल शुरू की। पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने महिलाओं की अलग राजनीतिक पहचान बनाने में मदद की। अंतत जीविका दीदी के रूप में रोजगार सृजन ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया।

लालू का दौर (1990-2005) सामाजिक संघर्ष के चलते उथल-पुथल से भरा हुआ था। राज्य के कुछ क्षेत्रों में नक्सलवादियों का वर्चस्व, जातीय सेनाओं का उदय और विस्तार, सामूहिक हत्या और राजनीति संरक्षित अराजक समूहों का दबदबा उनके दौर की दुस्वप्न गाथा बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव अभियान में इसे ही 'जंगल राज' का नाम दिया। लालू अब राजनीति में निष्क्रिय हैं, लेकिन उनके पुत्र तेजस्वी यादव को उसका जवाब भी देना पड़ रहा है और नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यह एक बड़ा कारण है, जिसके चलते बिहारी उद्योगपतियों ने कभी बिहार की तरफ नहीं देखा। चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, बिहार में सरकार की परीक्षा अब इन्हीं मानदंडों पर होगी। अब कोई नेता यह कह कर शायद युवा पीढ़ी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। जमीन तो है, नीयत ठीक करने और औद्योगिक दृष्टि की जरूरत है।

ममता की चुनौती, ममता को चुनौती

बिहार में तो एस.आई.आर. सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट था, असली प्रयोग तो बंगाल में होने वाला है। तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी हार जाएंगी? क्या ममता को हराना इतना आसान है? बंगाल में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में होने है और अभी से चुनावी मौसम शुरू हो गया है। अगले 2-3 महीनों में मौसम बिगड़ना तय है, लिहाजा चुनाव से संबंधित दलों को पेटी बांध लेनी चाहिए। भाजपा की एन.डी.ए. सरकार के पास धनबल है, नेताओं की फौज है, बेहतर रणनीतिकार है, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, महिलाओं में लोकप्रिय है, जीत का जज्बा है, मुस्लिम-दुखहदुओं को खुश रखा है। ऐसे में मुकाबला कड़ा और नजदीकी का हो सकता है। आमतौर पर कहा जा रहा है कि 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक वोट संदिग्ध हैं। ममता इसे समझ रही हैं। भाजपा के बंगाल के नेता ऐसा संकेत दे रहे हैं। पिछले 10 सालों को देखा जाए तो भाजपा का ग्राफ तेजी से बढ़ा है लेकिन ममता बनर्जी की पकड़ में भी कोई कमी नहीं आई। 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 10 फीसदी वोट मिले थे और सिर्फ तीन सीटें ही जीती जा सकी थीं। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में 3 गुना बढ़कर वोट फीसदी 30 प्रतिशत हो जाता है। सीटों की संख्या 3 से बढ़कर 77 हो जाती है। उधर ममता बनर्जी 2016 का चुनाव दो-तिहाई मतों से और 2021 में तीन-चौथाई मतों से जीतती है। 2021 में ममता को 2 करोड़ 87 लाख वोट मिलते हैं। भाजपा को 2 करोड़ 28 लाख वोट मिलते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी को 2 करोड़ 75 लाख वोट मिलते हैं। 42 में से 29 लोकसभा सीटें कब्जे में आती हैं। उधर भाजपा 12 सीटों पर सिमट जाती है, 2019 में 18 सीटें थीं। लेकिन भाजपा का वोट 2 करोड़ 33 लाख हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ममता और मोदी में वोटों का फासला 2021 के 59 लाख से घटकर 42 लाख ही रह जाता है। ऐसे में अगर 20-22 लाख वोट इधर-उधर हुए तो ममता का खेल बिगड़ सकता है और अगर सच में 1 करोड़ वोट कट गए तो बंगाल में बिहार से भी बड़ी सुनामी आ सकती है। अब भाजपा 30 फीसदी तक तो पहुंच गई लेकिन करीब 47 फीसदी वाली ममता को इस संख्या से हराया नहीं जा सकता। जब तक ममता बनर्जी के सुरक्षित वोट बैंक में सेंधमारी नहीं होगी, तब तक भाजपा का सत्ता में आना कठिन लगता है। वाम दलों और कांग्रेस का वोटर जो भाजपा के साथ चला गया था, वह वहीं टिका रहेगा, यह कहना भी मुश्किल नजर आता है। लेकिन ममता क्या ऐसा होने देंगी? सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एन.डी.ए. की सरकार थी लेकिन बंगाल में ममता की सरकार है। ऐसे में अपनी मर्जी से एस.आई.आर. करवाना संभव नहीं होगा। ममता दो मोर्चों पर सक्रिय नजर आती हैं। एक, कम से कम वोट कटें। दो, पूरी तरह से ठोक-पीट कर ही नए वोटर के नाम जोड़े जाएं। चुनाव आयोग का नया टैंडर ममता को परेशान कर रहा है। आयोग ने 1000 डाटा एंट्री आपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डिवेलपर अनुबंध के आधार पर भर्ती करने का फैसला किया है। उन्हें 1 साल के लिए रखा जाएगा। ममता ने इसका विरोध किया है। अब मतदाता का फार्म कैसा भरा जाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि डाटा एंट्री क्या की जाती है।

उसी के आधार पर वोटर का नाम स्वीकृत होगा या खारिज हो जाएगा। इस मुद्दे पर टी.एम.सी. के 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। भाजपा जानती है कि वह बिहार की तरह महिलाओं के लिए दस हजारी योजना पर बंगाल में अमल नहीं कर सकती क्योंकि वहां उसकी सरकार नहीं है।

देश भर के लिए कोई योजना लागू कर के ही वह बंगाल की महिलाओं तक पहुंच सकती है। वित्तीय हालत देखते हुए ऐसा संभव नहीं है। वैसे भी ई.डी. के राडार पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर करीब 10 प्रमुख सांसद और ममता मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। क्या अगले 2 महीनों में ई.डी. ओवर टाइम करती नजर आएगी? भाजपा बंगाल में हिंदुत्व और विकास का घोल परोसती रही है। बंगाल में करीब 30 फीसदी मुस्लिम हैं और भाजपा के लिए हिंदू मुस्लिम करना आसान होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। बंगाल में आमतौर पर हिन्दू धर्मनिरपेक्ष रहा है। ऐसे में विरोधी वोट पर एस.आई.आर. की कुल्हाड़ी चलाना आसान उपाय है। लेकिन भाजपा इसके साथ-साथ ममता को बंगाली अस्मिता के हथियार का तोड़ निकालने में लगी है। बंगाल में बाहरी बनाम बंगाल की बेटी के बीच चुनाव का नैरेटिव ममता स्थापित करती रही हैं। इस बार भाजपा भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जरिए सेंध लगाने की कोशिश में है। उसका कहना है कि बंगाल की जनता को आक्रामक अंदाज में यह समझाने की कोशिश होगी कि उनके मुखर्जी बंगाल की मिट्टी के ही मानुष थे। ऐसे में उन पर बाहरी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ममता बनर्जी भाजपा की इस चाल को पहले ही समझ गई थीं। उन्होंने दुर्गा पूजा के मौके पर लगने वाले पंडालों के लिए जमकर पैसा देना शुरू किया। अगर मौलवियों का मानदेय बढ़ाया तो पुजारियों के मानदेय में भी उतना ही इजाफा किया। पिछले लोकसभा चुनावों में तो ममता चुनावी सभाओं में चंडी पाठ करती नजर आई थीं। भाजपा का हिंदू कार्ड तो लोकसभा चुनावों में पिट गया या यूं कहा जाए कि उम्मीद के मुताबिक चला नहीं लेकिन विधानसभा चुनावों में भाजपा संघ के साथ मिलकर इस कार्ड को फिर से भुनाने के फेर में है। लेकिन टी.एम.सी. में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत है। ममता इस पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी ने इस चोरी-चकारी को बड़ा मुद्दा बनाया था। ममता ने तब कुछ जगह कार्यकर्ताओं से रिश्वत की रकम लौटाई भी थी लेकिन यह काम एक हद से ज्यादा पूरा नहीं हुआ। ममता बनर्जी के खिलाफ यह मामला तूल पकड़ सकता है। ममता बनर्जी ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए ढेरों योजनाएं चला रखी हैं। भाजपा इन योजनाओं में भ्रष्टाचार और योजना से छूटे हुए वोटरों को भी टारगेट पर ले रही है। कुल मिलाकर मुकाबला तगड़ा होने वाला है। ममता अगर मोदी को चुनौती दे रही है तो ममता को मोदी से चुनौती भी मिल रही है।-विजय विद्रोही

विलुप्त होती मोहल्ला संस्कृति

'हाई-राइज सोसायटी किसी जेल जैसी लगती है। घर से बाहर निकलो तो बस सीमेंट की दीवारें है, लिफ्ट में चढ़ो तो अजनबी चेहरों की चुप्पी।' शहरी विकास का खोखलापन उजागर करता एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर खासा चर्चित रहा। एकाकीपन से जूझती महिला के हृदय की व्यथा जग-जाहिर करता यह वीडियो दरअसल, आधुनिक युग की कटु वास्तविकता है, जिसे निदा फाजली ने कुछ यूं बयां किया था- हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी।। वीडियो में तन्हाई की कसक है, जिसे अमूमन आज हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। कारण स्पष्ट है, बदलते परिवेश के साथ हमारी प्राथमिकताएं भी बदलीं। संतुष्टि से इतर हम संपन्नता में जिंदगी तलाशने लगे। व्यस्तताओं व विलासिता में बढ़ते रुझान ने हमें हमारे उस सामाजिक दायरे से अलग-थलग कर डाला, जिसे मोहल्ला संस्कृति का नाम दिया गया था। विभिन्न परिवारों को एकसूत्र में पिरोती इस संस्कृति में सभी के सुख-दुख साझे थे। किसी भी घर में बड़ों की आवाज गूंजती तो आस-पड़ोस में अपनापन जताते नाते-रिश्ते स्वयं ही सृजित हो जाते। शादी-ब्याह के ढोल की थाप पूरे मोहल्ले को उल्लसित कर डालती। पारस्परिक परामर्श बड़ी से बड़ी समस्याएं चुटकी में सुलझा देता। कुल मिलाकर भावनात्मक लगाव ही इस संस्कृति की विलक्षण पहचान था। इसी थीम पर निर्मित आधुनिक फ्लैट संस्कृति का जायजा लें तो स्थिति सर्वथा विपरीत नजर आएगी। दीवारें परस्पर सटी होने के बावजूद संवेदनात्मक जुड़ाव नदारद महसूस होगा। शब्द शालीन, मगर अजनबीपन का आभास लिए। संक्षेप में, हमारा वजूद मोहल्ला संस्कृति की उदारवादी 'हम' प्रवृति से सिमटकर 'मैं' तक जा पहुंचा है। यही कारण है कि वर्तमान में अवसाद व आत्महत्या के मामले अपेक्षाकृत बढ़ चुके हैं, वह भी उस दौर में, जब तकनीकी साधनों के माध्यम से लोगों से संपर्क साधना पहले की बजाय कहीं सरल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के सोशल कनैक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व का हर छठा व्यक्ति खुद को सामाजिक रूप से एकाकी महसूस कर रहा है। अकेलापन प्रतिवर्ष 8 लाख 70 हजार से अधिक लोगों का जीवन लील रहा है। प्रति घंटे 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु का कारण एकाकीपन रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा अकेलापन शिक्षा, रोजगार तथा अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। शाब्दिक भ्रम से उबरने हेतु अकेलेपन तथा सामाजिक अलगाव की परिभाषा में अंतर जानना भी आवश्यक है। रिपोर्ट के अनुसार, अकेलापन वह पीड़ा है जो अपेक्षित सामाजिक जुड़ाव नहीं मिलने पर महसूस होती है, जबकि सामाजिक अलगाव की स्थिति में व्यक्ति के पास संबंधों का ही अभाव होता है। यह समस्या कमोबेश समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रही है लेकिन युवाओं, बुजुर्गों तथा गरीब देशों में रहने वाले लोगों में इसका प्रभाव सर्वाधिक देखने में आया। एक रिपोर्ट के तहत, 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किशोर अकेले हैं। अफ्रीका में 12.7 प्रतिशत किशोर अकेलेपन का अनुभव करते हैं, जबकि यूरोप में यह दर 5.3 प्रतिशत है। भारत में भी यह समस्या दिनों-दिन बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर हर चौथा बुजुर्ग अकेलेपन की समस्या से पीड़ित है, जिस कारण मानसिक दबाव बढ़ा है। बुजुर्गों में अकेलेपन के कारण मनोभ्रंश विकसित होने का खतरा 50 प्रतिशत ज्यादा होता है।

बौद्धिक प्रदूषण और नशे के विरुद्ध सामाजिक उत्तरदायित्व -21वीं सदी की दो अदृश्य वैश्विक चुनौतियाँ

वैश्विक स्तरपर 21वीं सदी मानव सभ्यता को तकनीक, विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊँचाइयों तक ले जा रही है, लेकिन इसी प्रगति के समानांतर दुनियाँ दो ऐसी अदृश्य और बढ़ती चुनौतियों से जूझ रही है, जिनका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक, गहरा और दीर्घकालिक स्तरपर भविष्य के निर्माता युवाओं पर पड़ रहा है है, वो है बौद्धिक प्रदूषण और नशा जिसके खिलाफ समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बन गई है। पर्यावरणीय प्रदूषण के समाधान की दिशा में वैश्विक तंत्र,कानून, विज्ञान और तकनीक सतत सुधार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हवा, पानी, प्लास्टिक, कचरा, औद्योगिक उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट को नियंत्रित करने के लिए नीतियाँ, शोध, संस्थान और संसाधन मौजूद हैं, लेकिन बौद्धिक प्रदूषण और नशे के विरुद्ध सामाजिक उत्तरदायित्व उतनी तेजी और सटीकता से नहीं बन पा रहा है। मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि जब प्रश्न मानव चेतना, विचार, मूल्य और मानसिकता के प्रदूषण का हो,तो समाधान पारंपरिक नहीं रह जाता, बल्कि वह नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेपों पर आधारित हो जाता है। यही कारण है कि बौद्धिक प्रदूषण किसी भी सभ्यता को भीतर से कमजोर करने वाला सबसे खतरनाक अदृश्य रोग बन चुका है, जिसकी तुलना किसी भी भौतिक प्रदूषण से नहीं की जा सकती। इसी प्रकार नशा आज केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जनसंख्या, परिवार, शिक्षा, अपराध, मानव संसाधन और राष्ट्रीय विकास से जुड़े बहुआयामी संकट का रूप ले चुका है। यह सोचना कि नशाखोरी रोकना केवल पुलिस, कानून या दंड व्यवस्था की जिम्मेदारी है, एक गलत और सीमित दृष्टिकोण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नशे के बढ़ते मामलों में 70 प्रतिशत जड़ें सामाजिक व्यवहार, वातावरण,परिवार, सांस्कृतिक प्रभाव और मानसिक तनाव से जुड़ी होती है, जबकि कानून केवल अंतिम चरण में हस्तक्षेप करता है। इसलिए नशे के खिलाफ लड़ाई वास्तव में समाज,परिवार शिक्षा तंत्र, स्वास्थ्य संस्थान, मीडिया, धार्मिक-सांस्कृतिक समुदायों और शासन प्रणाली इन सभी का संयुक्त युद्ध है। साथियों बात अगर हम बौद्धिक प्रदूषण एक अदृश्य खतरा और वैश्विक संकट है इसको समझने की करें तो बौद्धिक प्रदूषण को सरल शब्दों में परिभाषित किया जाए तो यह वह स्थिति है जब मनुष्य की सोच, समझ, विवेक, निर्णय-क्षमता और नैतिक चेतना गलत,भ्रमित, पक्षपातपूर्ण उग्र, हिंसक, असत्य या दुष्प्रभावित विचारों से प्रभावित हो जाती है। यह प्रदूषण किसी फैक्ट्री के धुएँ या वाहन के धुएँ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका नुकसान किसी भी वायु प्रदूषण से बड़ा हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति को विचारों, धारणाओं और सूचनाओं के भ्रमजाल में फँसा कर उसकी तार्किक क्षमता और सामाजिक चेतना को नष्ट कर देता है। फेक न्यूज, नफरत आधारित प्रचार, कट्टर राष्ट्रवाद, उग्रवाद, नस्लीय विभाजन, षड्यंत्र,धार्मिक उन्माद, डिजिटल हेरफेर, गलत सूचना, दुष्प्रचार, हेट स्पीच और सोशल मीडिया एल्गोरिदम के माध्यम से फैलने वाला भ्रम,आज दुनियाँ भर के देशों में बौद्धिक प्रदूषण के मुख्य स्रोत बन चुके हैं।तकनीक और ज्ञान की उपलब्धता जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी ही तेजी से मानव मन की ग्रहणशीलता पर अनियंत्रित सूचनाओं का बोझ बढ़ा है। इंटरनेट ने सूचना को लोकतांत्रिक बनाया, लेकिन उसी ने अज्ञान को भी संस्थागत रूप दे दिया। अब सत्य और असत्य में फर्क करना एक आम नागरिक के लिए पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। यह बौद्धिक धुंध न केवल व्यक्ति के विवेक को प्रभावित करती है, बल्कि लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और मानवीय मूल्यों को भी कमजोर करती है। इतिहास गवाह है कि सभ्यताएँ बाहरी हमलों से कम, आंतरिक भ्रम, विभाजन, गलत विचारधारा और मानसिकप्रदूषण से अधिक टूटती हैं। इसी कारण बौद्धिक प्रदूषण मानवता के लिए एक साइलेंट ग्लोबल पैंडेमिक बनकर उभरा है। साथियों बात अगर हम क्या बौद्धिक प्रदूषण का समाधान संभव है? इसको समझने की करें तो, भौतिक प्रदूषण के समाधान स्पष्ट हैं, फिल्टर, रिसाइक्लिंग प्रतिबंध, तकनीक, कानून और स्वच्छ ऊर्जा। लेकिन बौद्धिक प्रदूषण का समाधान विज्ञान नहीं, बल्कि चेतना, शिक्षा, नैतिकता, संवाद, मीडिया जिम्मेदारी और सामाजिक संरचना के सुधार में निहित है। यह प्रदूषण तब पनपता है जब समाज तर्क की जगह अंधानुकरण को अपनाता है,जब शिक्षा ज्ञान की जगह अंकों पर आधारित हो जाती है, जब मीडिया सूचना की जगह सनसनी को बेचने लगता है,और जब तकनीक सत्य की जगह भ्रम को अधिक प्रोत्साहित करती है। इसलिए समाधान बहुस्तरीय होना चाहिए, समालोचनात्मक सोच पर आधारित शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तथ्य-आधारित संवाद, मीडिया पारदर्शिता, सामाजिक संवाद, युवा नेतृत्व और बहु सांस्कृतिक सम्मान की संस्कृति। बौद्धिक प्रदूषण को किसी एक संस्था, कानून या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक चुनौती है। यह समाधान तभी संभव है जब वैश्विक समाज सत्य को मूल्य के रूप में स्वीकार करें, संवाद को संघर्ष से ऊपर रखें और शिक्षा को नौकरी नहीं बल्कि चेतना- निर्माण का माध्यम समझे। हर परिवार,हर स्कूल,हर विश्वविद्यालय और हर राष्ट्र को यह स्वीकार करना होगा कि विचारों की शुद्धता सभ्यता के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यदि मन प्रदूषित है तो प्रगति विनाश बन जाती है, और यदि विचार निर्मल है तो मानवता हर संकट का समाधान ढूंढ सकती है। साथियों बात अगर हम नशे के खिलाफ लड़ाई,केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं,एक सामाजिक युद्ध है इसको समझने की करें तो, नशा किसी एक देश, समाज, धर्म, वर्ग या उम्र की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक महामारी है। ड्रग्स, शराब, तंबाकू, सिंथेटिक नशीले पदार्थ, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का दुरुपयोग, गेमिंग और डिजिटल एडिक्शन ये सभी आधुनिक नशे के विस्तृत रूप हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनियाँ में हर वर्ष 3 करोड़ से अधिक लोग नशे से सीधे प्रभावित होते हैं और लाखों की मौतें इससे जुड़ी बीमारियों और अपराधों के माध्यम से होती हैं। नशा केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं,बल्कि अपराध, सीमा पार तस्करी, आतंकवाद, मानव तस्करी,घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएँ, आत्महत्या, स्कूल ड्रॉप -आउट, बेरोजगारी और आर्थिक क्षति जैसे व्यापक संकटों को जन्म देता है।यह मान लेना कि इस समस्या को पुलिस, कानून और दंडात्मक व्यवस्था अकेले समाप्त कर देगी, एक बड़ी भूल है। पुलिस केवल अपराध को रोक सकती है, आदत को नहीं; कानून केवल सजा दे सकता है, मानसिकता को नहीं; और दंड केवल भय पैदा कर सकता है, समाधान नहीं। नशे की जड़ें मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव, पारिवारिक टूटन, बेरोजगारी, अकेलापन, हिंसा, निराशा, असमानता और गलत संगत में छिपी होती है। इसलिए नशा एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक और सांस्कृतिक संकट है, जिसका समाधान केवल दंड नहीं बल्कि पुनर्वास, संवाद,शिक्षा,सामुदायिक सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व में है। परिवारों को प्रारंभिक पहचान सीखनी होगी, स्कूलों को निवारक शिक्षा देनी होगी,मीडिया को नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी, स्वास्थ्य संस्थानों को उपचार और परामर्श को केंद्र में रखना होगा, और समाज को नशाखोर को अपराधी नहीं बल्कि रोगी के रूप में समझकर उसके पुनर्निर्माण का प्रयास करना होगा। यह संघर्ष तभी जीता जा सकता है जब समाज नशे को शर्म नहीं, समस्या माने; अपराध नहीं, बीमारी समझे; और दंड नहीं, उपचार को प्राथमिकता दे। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बौद्धिक प्रदूषण और नशा दोनों अदृश्य संकट हैं, लेकिन इनके प्रभाव दृश्यमान,गहरे और विनाशकारी हैं। पहला मानव की सोच को विकृत करता है, दूसरा शरीर और जीवन को नष्ट करता है। एक सभ्यता को भीतर से गिराता है, दूसरा समाज की ऊर्जा और युवा शक्ति को खोखला करता है। और सबसे महत्वपूर्ण,इन दोनों से लड़ाई केवल कानून या सरकार नहीं जीत सकती। यह मानवता का संघर्ष है, समाज का दायित्व है, शिक्षा का मिशन है और प्रत्येक नागरिक की जागरूक भूमिका का विषय है। यदि विचार शुद्ध हों और समाज जिम्मेदार हो, तो मानवता इन दोनों संकटों पर विजय पा सकती है। लेकिन यदि हम मौन रहे, उदासीन रहे या जिम्मेदारी टालते रहे,तो प्रगति के बावजूद सभ्यता का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कमल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया संपादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/33882)

मेजा ऊर्जा निगम के अधिकारियों की तानाशाही से किसान परेशान

मेजा प्रयागराज।

- किसानों व बेरोजगारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना देने जा रहे कांग्रेस नेता नमस्ते यादव को एनटीपीसी गेट पर किया गिरफ्तार
- पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस नेता सहित उनके समर्थक किसानों के खिलाफ 151 के तहत किया गया कार्रवाही , न्यायालय ले गयी पुलिस

यमुनापार मेजा ऊर्जा निगम में किसानों व बेरोजगारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मेजा ऊर्जा निगम के मुख्य द्वार पर धरना देने जा रहे कांग्रेस नेता जितेन्द्र उर्फ नमस्ते यादव सहित कुछ किसानों को मुख्य द्वार से पहले एनटीपीसी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उन्हें तथा उनके साथ रहे समर्थकों के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय ले गई। डीसीपी यमुनापार विवेक चन्द यादव ने बताया कि बिना अनुमति के कांग्रेस नेता व उनके समर्थकों का धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी के खिलाफ 151 के तहत लिखापढ़ी की गई है। डीसीपी ने बताया कि धरना करने से पहले कांग्रेस नेता नमस्ते यादव व उनके साथ धरना देने वाले किसानों को वार्ता के लिए एसीपी कार्यालय मेजा बुलाया गया था, रविवार को होने वाली इस बैठक में मेजा ऊर्जा निगम के अधिकारी तो पहुंचे लेकिन किसान नेता व

कांग्रेस नेता नमस्ते यादव नहीं पहुंचे। जिससे किसानों की समस्या क्या है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दोपहर बारह बजे के लगभग कांग्रेस नेता कुछ समर्थकों के साथ मेजा ऊर्जा निगम के मुख्य द्वार पर धरना देने के लिए चले तो रास्ते में जगह-जगह रही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मुख्य द्वार पर नहीं पहुंच सके।

किसान नेता ने बताया कि किसानों की जमीन व उजाड़े गए मकान का सही मुआवजा नहीं दिया जा सका।उचित मुआवजा के बिना कोई निर्माण कार्य न किया जाय । जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है। उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। एनटीपीसी के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गाँवों को 24 घन्टे मुफ्त बिजली दी जाय। राख व धुएं से हो रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। आईआईटी बीटेक व पॉलीटेक्निक का शिक्षित बेरोजगार नव युवकों को मेजा ऊर्जा निगम में सीधी नियुक्ति दी जाय। साथ ही किसानों पर कुछ वर्षों पहले चलाये गए मुकदमे वापस लिए जाएं। अस्पताल खोलकर मुफ्त इलाज किया जाय। निगम ने कहा, नहीं हो रहा कोई नवनिर्माण मेजा। मेजा ऊर्जा निगम सीएसआर के एजीएम एचआर विवेक चंद्रा ने बताया कि जिस जमीन के लिए किसान धरना देने की बात कर रहे हैं, वह जमीन सरकारी है। जिस पर कुछ किसान अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रखे थे। इस जमीन का मुआवजा शासन के निर्देश पर दिया जा सकता है। अभी जमीन पर नव निर्माण का काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए धरना प्रदर्शन का कोई औचित्य ही नहीं है। दो दिन पूर्व 25 नवम्बर को पुलिस प्रशासन ने मेजा ऊर्जा निगम के अधिकारियों व किसानों के बीच वार्ता के लिए एसीपी कार्यालय में बुलाया था। इस वार्ता में मेजा ऊर्जा निगम के अधिकारी तो पहुंचे, लेकिन किसान नेता व कांग्रेस नेता नहीं पहुंचे। जिससे वार्ता नहीं हो सकी। शासन प्रशासन का जो भीनिर्देश है, उसका अनुपालन किया जाएगा। बिना गाइड लाइन के किसी मुद्दे पर बात करना उचित नहीं है। किसानों की मांग हैं कि सभी किसानों को समान मुआवजा व रोजगार दिया जाय।

राष्ट्रीय वॉलीबाल प्रतियोगिता की खेल गाड़ी का प्रयागराज आगमन पर भव्य स्वागत

- काशी में होने वाली 72वीं सीनियर पुरुष व महिला नेशनल वॉलीबाल चैंपियनशिप की खेल गाड़ी आठवें दिन पहुँची प्रयागराज

मेजा,प्रयागराज ।

अभिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्योहल प्रयागराज में डिस्ट्रिक्ट वॉलीबाल एसोसिएशन,प्रयागराज के पदाधिकारियों और जनपद के वॉलीबाल खिलाड़ियों ने वाराणसी जनपद में होने वाली 72वीं सीनियर पुरुष व महिला नेशनल वॉलीबाल चैंपियनशिप की खेल गाड़ी,(रथ यात्रा) का प्रयागराज पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी में होने वाली 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबाल चैंपियनशिप की आयोजन समिति एवं जिला वॉलीबाल संघ वाराणसी के पदाधिकारीगण जोकि चैंपियनशिप के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में जाकर जनपद के खेल संघों के अध्यक्ष व सचिव तथा क्रीड़ाधिकारीयों को आमंत्रण-पत्र सौंपकर काशी आने का आग्रह किया।

खेल गाड़ी टूर का आठवें दिन 27 नवंबर को प्रयागराज जनपद में आगमन हुआ। राष्ट्रीय वॉलीबाल प्रतियोगिता के आयोजन समिति की ओर से वाराणसी जिला वॉलीबाल संघ के अध्यक्ष प्रो.डॉ.अभिमन्यु सिंह ने डिस्ट्रिक्ट वॉलीबाल एसोसिएशन,प्रयागराज के पदाधिकारियों को आमंत्रण-पत्र सौंपा और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रयागराज मंडल प्रेम कुमार जी का आमंत्रण पत्र म्योहाल प्रभारी / जिला क्रीड़ा अधिकारी मनीष गुप्ता जी को सौंपा।

डीवीए प्रयागराज के पदाधिकारियों ने अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंटकर डॉ.अभिमन्यु सिंह का प्रयागराज आगमन पर स्वागत किया।

डॉ.अभिमन्यु सिंह ने वॉलीबाल ग्राउंड पर जाकर खिलाड़ियों से मुलाकात की। उक्त अवसर पर अल्ताफ अली, फूलचंद गुप्ता, मुकेश शुक्ला, विजया सिंह, म्योहाल वॉलीबाल कोच डॉ.वीर सिंह, योगेश शर्मा, गुलशन हासमी, असफाक अहमद, रवि वर्मा आदि लोग उपस्थित रहें।।

आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की उठाई मांग

क्षत्रिय समाज ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

मुरादाबाद।

शुक्रवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले क्षत्रिय समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सपा प्रवक्ता मनोज यादव द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्षत्रिय समाज के प्रति की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में था। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और मनोज यादव तथा आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मनोज यादव की टिप्पणियाँ क्षत्रिय समाज का अपमान हैं। उन्होंने सरकार से सपा प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज करने और उन्हें माफी मांगने के लिए बाध्य करने की मांग की। इसके अतिरिक्त, आईएएस संतोष वर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की मांग की गई। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान मनोज यादव मुर्दाबाद, क्षत्रिय समाज की जय और संतोष वर्मा को बर्खास्त करो जैसे नारे लगाए गए। समाज के लोगों ने हाथों में बड़े बैनर, तख्तियां और झंडे लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर किया जाएगा। प्रदर्शन स्थल पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिलाधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि इस प्रकरण की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राज्य आपदा मोचक बल लखनऊ रवाना

मुरादाबाद। कलक्ट्रेट परिसर से आपदा मित्र योजना के तहत प्रथम चरण में 49 स्वयं सेवकों को आपदा मित्र प्रशिक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर राज्य आपदा मोचक बल (एस.डी.आर.एफ.) लखनऊ के लिए रवाना किया गया। यह आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त कर जनपद में होने वाली आपदाओं का सामना करने में सक्षम बनेंगें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपदा मित्र जनपद में फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगें। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, संभल द्वारा एन.सी.सी., एन.एस.एस., नागरिक सुरक्षा, अग्नि षमन से स्वयं सेवकों का चयन किया गया है। इन सभी को स्वयं सेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 29.11.2025 से 10.12.2025 के लिए एस.डी.आर.एफ. लखनऊ भेजा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सामुदायिक जागरूकता से आपदाओं के समय होने वाले नुकसान को कम करने लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिषा निर्देषों पर इन स्वयं सेवकों को आपदा प्रबंधन, आपदा पूर्व तैयारी, भूकंप सुरक्षा, खोज एवं बचाव, अग्नि सुरक्षा, बरसात के मौसम में बाढ़, आकाषीय बिजली, सी.पी.आर. आदि हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रषिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद इन्हें आपातकालीन किट, लाईटर, बहु उपयोगी रस्सी, कटर, सीटी आदि उपलब्ध कराई जायेगी। इस अवसर पर श्री सौरभ पाण्डेय डिप्टी कलेक्टर, श्री अच्युत कुमार जिला आपदा प्रबंधन विषेशज्ञ तथा आपदा मित्र मौजूद रहे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सैनिक बंधु की बैठक संपन्न

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सेवानिवृत्त सैनिकों ने अपनी शिकायतें और समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा, जिनके संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया। सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा खतौनी में दर्ज अपने नाम को दुरुस्त कराने के संबंध में बताया कि राजस्व अभिलेखों में लतूर सिंह के स्थान पर लतूरी सिंह हो गया है। इसे संशोधित कराने के लिए उन्होंने कई बार तहसील में संपर्क किया है परंतु अब तक समाधान नहीं हो पाया है जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को फोन करके तत्काल दुरुस्त कराकर संशोधित खतौनी भेजने के लिए निर्देश दिए। इस प्रकार मौके पर ही शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान हो गया। इसी प्रकार एक अन्य सेवानिवृत्त सैनिक ने बताया कि नगर निगम मुरादाबाद में हाउस टेक्स के विवरण में उनका नाम गलत दर्ज है जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, नगर निगम में कई बार वे चक्कर लगा चुके हैं परंतु काम नहीं हो पा रहा है, जिलाधिकारी ने इस प्रकरण में भी अपर नगर आयुक्त को फोन करके प्रकरण को तत्काल निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया। सेवानिवृत्त सैनिक की पत्नी ने अपने जमीनी विवाद का मुद्दा भी जिलाधिकारी के समक्ष उठाया जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्राधिकारी पुलिस और तहसीलदार को प्राथमिकता से निस्तारण कराने के लिए निर्देश दिए। राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौके पर जमीन उपलब्ध न कराने के संबंध में शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसओसी चकबंदी को तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि

सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा खतौनी में दर्ज अपने नाम को दुरुस्त कराने के संबंध में बताया कि राजस्व अभिलेखों में लतूर सिंह के स्थान पर लतूरी सिंह हो गया है। इसे संशोधित कराने के लिए उन्होंने कई बार तहसील में संपर्क किया है परंतु अब तक समाधान नहीं हो पाया है जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को फोन करके तत्काल दुरुस्त कराकर संशोधित खतौनी भेजने के लिए निर्देश दिए।

सेवानिवृत्त सैनिकों की 02 शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण

लापरवाही बरतने वाले कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई करें। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त सैनिकों ने कहा कि प्रदेश के कुछ अन्य नगर निगम क्षेत्र में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए हाउस टैक्स माफ कर दिया गया है, जनपद मुरादाबाद में भी सेवानिवृत्त सैनिकों का हाउस टैक्स माफ किया जाए, जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में लिखित पत्र उपलब्ध करा दें ताकि नगर निगम को नियमानुसार कार्रवाई के लिए भेजा जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की सुविधा और सुरक्षा के साथ-साथ उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष संवेदनशीलता बरती जा रही है। भूतपूर्व सैनिकों की हर समस्या का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है, उन्होंने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ज्ञान स्वरूप को सभी शिकायतों और समस्याओं के निस्तारण की स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए निर्देश दिए।

इस अवसर पर एडीएम सिटी सुश्री ज्योति सिंह भी मौजूद रहीं।

लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अहम फैसले में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मौजूद डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर छीन ली है, जिनका इस्तेमाल अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, एमएचए के पास अब एलजी के पास पहले से मौजूद 100 करोड़ रुपये तक की स्कीम और प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की पावर होगी. इसी तरह, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को 20 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की फाइनेंशियल पावर एमएचए को दे दी गई है, जबकि चीफ इंजीनियर, डिपार्टमेंट हेड, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर शामिल है, को भी 3 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच के अलग-अलग काम को मंजूरी देने की डेलीगेटेड पावर का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के आधार पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने इस बारे में एक ऑर्डर जारी किया है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत 100 करोड़ रुपये तक की स्कीम/प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थी, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा. लेफ्टिनेंट गवर्नर की 100 करोड़ रुपये तक की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी और खर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की 20 करोड़ रुपये तक की मंजूरी देने की शक्तियों में भी बदलाव किया गया है. ये मंजूरी अब एमएचए देगा. सबसे जरूरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड और डिप्टी कमिश्नरों की 5 करोड़ रुपये तक के अलग-अलग कामों को मंजूरी देने की शक्तियों को वापस लेना है, जो एमएचए के पास चली गई थीं.
ये सभी अधिकारी लेह और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं, जिससे वे असल में काम नहीं कर रहे हैं. चुनाव में देरी के कारण लेह हिल काउंसिल पांच साल का टर्म पूरा करने के बाद खत्म हो गई है, जबकि कारगिल हिल काउंसिल बनी हुई है.
लेह हिल काउंसिल की शक्तियां डिप्टी कमिश्नर लेह को दे दी गई हैं. चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को एक के बाद एक 10 करोड़ रुपये और 3 करोड़ रुपये तक के अलग-अलग कामों को मंजूरी देने की पावर भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे दी गई है.
ऑर्डर में कहा गया है, प्रोजेक्ट्स/स्कीमों के अप्रेजल और अप्रूवल के सभी नए प्रपोजल जरूरी अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स को सबमिट किए जाएंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और खर्च की मंजूरी सहित नए प्रोजेक्ट्स/स्कीमों के अप्रेजल के लिए एमएचए को सबमिट किए जाने वाले सभी प्रपोजल प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, लद्दाख के जरिए भेजे जाएंगे. हालांकि, यह साफ किया गया कि सभी चल रही स्कीम/प्रोजेक्ट के काम, जिनमें वे काम भी शामिल है

-: टीएमसी का चुनाव आयोग पर खून का आरोप :-

40 मौतों की सूची देकर सीईसी ज्ञानेश कुमार से तीखे सवाल

नई दिल्ली।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 10 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक की और पश्चिम बंगाल तथा देश भर के अन्य राज्यों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। बैठक के दौरान, टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार से कहा कि उनके हाथ खून से सने हैं और सांसद डेरेक ओब्रायन के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के कारण मारे गए 40 लोगों की सूची सौंपी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री कुमार और उनकी टीम से मुलाकात की। हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के कारण मारे गए लगभग 40 लोगों की सूची सौंपी। हमने बैठक की शुरुआत यह कहकर की कि श्री कुमार और भारत के चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं। ओब्रायन के अलावा, राज्यसभा सांसद डोला सेन, साकेत गोखले, ममता ठाकुर और महुआ मोइत्रा भी बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं। टीएमसी सांसद ने कहा कि उन्होंने बैठक के दौरान कम से कम पाँच सवाल उठाए, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिला। हमने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से पाँच सवाल उठाए। हमें अपने पाँचों सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं मिला। यही हुआ। टीएमसी सांसद के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने दो घंटे की बैठक में 40 मिनट तक बिना रुके बात की और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सुना। टीएमसी राज्यसभा सांसद ममता ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने बैठक के दौरान उठाए गए सवालों पर बात की। टीएमसी सांसद ने पूछा कि अगर घुसपैठिए हैं, तो मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड को (एसआईआर प्रक्रिया में) क्यों शामिल नहीं किया गया है, और केवल पश्चिम बंगाल को ही शामिल किया गया है? वे कहते हैं कि वे मतदाता नहीं हैं और राज्यों में बंगालियों पर अत्याचार करते हैं। लोग सोचते हैं कि वे बांग्ला नहीं बोलते, और उन्हें बांग्लादेशी कहते हैं।

प्रदूषण पर संग्राम: राहुल गांधी का केंद्र पर कटाक्ष, बच्चों का दम घुट रहा, मोदी सरकार चुप क्यों?

माएं मुझसे कहती हैं- बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे, संसद में चर्चा हो

नई दिल्ली।

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली की बढ़ती वायु प्रदूषण समस्या पर तुरंत और विस्तृत बहस की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजधानी की हवा बेहद खराब है और यह स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं तब सरकार की तरफ से जिम्मेदारी और तत्परता क्यों नहीं दिख रही। कांग्रेस नेता ने अपने आवास पर कुछ माताओं से मुलाकात की और उनकी बातों का वीडियो साझा किया। कई महिलाओं ने चिंता जताई कि प्रदूषण से उनके बच्चों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।
राहुल ने कहा, हर मां एक ही बात कहती है उसका बच्चा जहरीली हवा में पल रहा है। बच्चे थक चुके हैं, डरते हैं और गुस्सा भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत के बच्चे सामने ही घुट रहे हैं। मोदी जी आप चुप कैसे रह सकते हैं? वीडियो में राहुल ने कहा कि दिल्ली में सबसे

संसद में चर्चा हो, एक्शन प्लान बनाए सरकार; दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने की मांग

गरीब और सबसे अमीर दोनों ही प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ शक्तिशाली हितधारक प्रदूषण से फायदा लेते हैं और यही वजह है कि समस्या बनी रहती है। आम नागरिक संगठित नहीं हैं, इसलिए उनकी आवाज राजनीतिक असर नहीं डाल पाती। एक अन्य महिला ने कहा कि यह एक पुरानी और गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सलाह या निर्देश नहीं आते। उन्होंने पूछा कि पूरी पीढ़ी प्रभावित हो रही है, फिर सरकार चुप क्यों है? राहुल ने कहा कि वे इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे भी उसी हवा में सांस लेते हैं और समस्या किसी से छिपी नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह 8 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 384 दर्ज किया गया।
27 नवंबर को शाम 4 बजे शहर का एक्यूआई 377 दर्ज किया गया था। मामूली गिरावट के बावजूद, शहर की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रही।

भीषण हादसा: खनिज लदा था डंपर

परिवार पर कहर बनकर बरसी मौत, बच्ची समेत सात की मौत

सहारनपुर ।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सहारनपुर के सैय्यद माजरा गांव का रहने वाला एक परिवार कार से कहीं जा रहा था। जैसे ही कार गांव की सीमा पार करके एक्सप्रेसवे पर पहुंची, उसी समय देहरादून की दिशा से तेज रफ्तार में खनिज से भरा एक डंपर आ रहा था। जो अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार को अचानक सामने देखकर डंपर चालक ने ब्रेक लगाए, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया। नियंत्रण खोने पर डंपर सीधे कार के ऊपर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह डंपर के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, कार में मौजूद सात लोगों में दो बच्चे भी शामिल हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कड़ी मशक्कत के बाद निकलवाया। जेसीबी की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को डंपर के नीचे से निकलवाया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।

अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 128 हुआ, जली हुई इमारतों से अभी भी मिल रहे शव

हांगकांग। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में लगी आग में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 128 हो गया है। शुक्रवार को आग से प्रभावित इमारतों में तलाशी अभियान के दौरान कई और शव मिले, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया। अग्निशमन विभाग अब शुक्रवार को तलाशी अभियान के आखिरी चरण में है और उसके बाद अभियान समाप्त कर दिया जाएगा। अग्निशमन दल के लोग सबसे ज्यादा उन इमारतों की तलाशी पर फोकस कर रहे हैं, जहां से सबसे ज्यादा कॉल आए थे, लेकिन अग्निशमन दल के लोग पहुंच नहीं पाए थे। हांगकांग के सुरक्षा सचिव क्रिस तांग ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जली हुई इमारतों से शव बरामद हो रहे हैं और मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।

बड़ा हादसा : दक्षिणी थाईलैंड में भयानक बाढ़ ने मचाई तबाही! 145 की मौत, हजारों लोग हुए बेघर

थाईलैंड।

दक्षिणी थाईलैंड में आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। अधिकारियों के अनुसार, अब तक 145 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पानी उतरने के साथ हालात और भयावह रूप दिखा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ने बताया कि लगातार कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश से 12 प्रांतों में 1.2 मिलियन घर और करीब 3.6 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। यह बाढ़ पिछले कई वर्षों में आई सबसे गंभीर आपदाओं में से एक मानी जा रही है। सरकार के प्रवक्ता सिरिपोंग अंगकासा कुलकियात के अनुसार, सबसे ज्यादा नुकसान सोंगखला प्रांत में हुआ है, जहां 110 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जैसे-जैसे पानी नीचे जा रहा है, रेस्क्यू टीमें दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचकर और भी शव बरामद कर रही हैं। हाट याई, जो दक्षिणी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है, वहीं कई दिन तक पानी भरा रहने के बाद अब राहतकर्मियों को बड़ी संख्या में शव मिले हैं। आपदा एजेंसी ने बताया कि अधिकांश जगहों पर पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कुछ इलाके अब भी बुरी तरह डूबे हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भले ही बारिश कम हुई हो, लेकिन आने वाले दिनों में दक्षिणी इलाकों में आंधी-तूफान का खतरा बना हुआ है।

कर्नाटक सीएम की दौड़ में डीके शिवकुमार का यू-टर्न! कहा- मुझे कुछ नहीं चाहिए, पार्टी का फैसला सर्वोपरि

नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर मचे घमासान के बीच, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को दोहराया कि वह किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहते और पार्टी आलाकमान ही मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेगा। सत्ता संघर्ष के बीच वोक्कालिगा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु नंजावधूता स्वामीजी से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर, शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस उनका समुदाय है और वह राज्य के सभी समुदायों को समान रूप से देखते हैं। उपमुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। मेरी पार्टी फैसला लेगी। मैं किसी भी तरह का सामुदायिक कोण नहीं चाहता। कांग्रेस मेरा समुदाय है और मेरा प्यार समाज के सभी वर्गों के लिए है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की बैठक में मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेने की

अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन शिवकुमार ने कहा कि वह संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कर्नाटक के किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा। यह हमारा मंदिर है। कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है और दिल्ली हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगी। जब मुझे, पार्टी नेताओं और मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा, तो हम वहाँ जाएंगे। मुझे दिल्ली में बहुत काम है। संसद का शीतकालीन सत्र आ रहा है और मुझे सांसदों से मिलना है क्योंकि उन्हें हमारी कुछ परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है। मेरे मुख्यमंत्री (केंद्र के साथ) इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मक्के का मुद्दा भी है। केंद्र सरकार किसानों का समर्थन या मदद नहीं कर रही है. हमने फैक्टरी मालिकों की एक बैठक बुलाने का फैसला किया है। हम अनुरोध करते हैं कि दिल्ली इसे अपने हाथ में ले ले और आप इसे खरीद लें। कर्नाटक में नेतृत्व विवाद नवंबर में कांग्रेस सरकार के अपने कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुँचने के बाद शुरू हुआ। इस बीच, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा कि उन्होंने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात इसलिए की क्योंकि उन्हें प्रशासनिक समस्या थी।

मिर्जापुर में बेकाबू कार का कहर: पिता-पुत्र सहित चार की मौत, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चीख-पुकार

मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले में शुक्रवार सुबह सड़क दुर्घटना में एक कार में सवार पिता-पुत्र समेत चार लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अमर बहादुर सिंह ने बताया कि कछवा थाना क्षेत्र में सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कटका में सड़क हादसे में एक कार में सवार पिता-पुत्र समेत चार लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। उन्होंने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी की ओर से जा रही एक अनियंत्रित कार सड़क पार कर रहे दो लोगों को रौंदते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। सीओ ने बताया कि हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान श्याम कृष्ण यादव (55) और उनके बेटे अनुराग यादव (30) के रूप में हुई जो कार में सवार थे। वे प्रयागराज के सोरांव के रहने वाले थे। हादसे में मारे गए दो अन्य लोगों की पहचान सरोज (40) और भोलू (35) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

एसआईआर प्रक्रिया पर पल्लवी पटेल ने उठाए सवाल, कहा- ये केंद्र सरकार का एक नया जुमला

गोंडा।

सपा के टिकट पर सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने गोंडा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। पल्लवी पटेल ने कहा कि वह इस देश की नागरिक हैं, उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं और वह वर्षों से मताधिकार का प्रयोग करती आ रही हैं। ऐसे में उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं तो फिर एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। उन्होंने अदालत के निर्देशों का सम्मान करने की बात कही, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट कुछ भी कहे, मैं स्कूल फॉर्म नहीं भरूंगी। पल्लवी पटेल ने एसआईआर प्रक्रिया को महिलाओं के आरक्षण की घोषणा जैसा बताया–जो कागज पर ही सीमित रही और जमीन पर लागू नहीं हो सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर केंद्र सरकार का एक नया जुमला है, जिसका उद्देश्य लोगों

के साथ न्याय करना नहीं, बल्कि उन्हें भ्रमित करना है। गौरतलब है कि देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर-घर जाकर दे रहे हैं और यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 99 फीसदी फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और अब फॉर्म संग्रह करने की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि यदि आप मतदाता हैं, तो अपना वर्तमान एपिक नंबर लिखें और 2002-2003 की एसआईआर के लिस्ट में आपका नाम है तो उसका विवरण फॉर्म के निचले हिस्से में दायीं ओर देखें और यदि आपका नाम नहीं है, तो अपने माता-पिता, दादा-दादी या फिर नाना-नानी जिनका भी 2002-2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, उसे फॉर्म के नीचे बाईं ओर लिखें और उनका वोटर कार्ड नंबर, मतदान केंद्र का नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आदि का उल्लेख करने के बाद आप अपने बीएलओ के पास फॉर्म को जमा कर दें उसके बाद आप का नाम लिस्ट में दर्ज हो जाएगा।

विकसित भारत 2047 का मार्ग 'वोकल फॉर लोकल'- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का रास्ता वोकल फॉर लोकल से होकर ही गुजरेगा। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब देश में बनी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होगा और लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री-संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत 2047 और वोकल फॉर लोकल के आह्वान

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से 'आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री- संपर्क अभियान' की शुरुआत की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रवनीत सिंह बिट्टू भी रहे मौजूद

को आमजन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाकर तथा ट्रेन में मौजूद यात्रियों से संपर्क कर 'आत्मनिर्भर भारत' के पत्रक वितरित किए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 12वीं-

13वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल 11 वर्षों में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोकल उत्पादों के उपयोग, उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को अपनाने से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा।

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में विश्वास रखा

उन्होंने रेलवे विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहे हैं। चंडीगढ़, पंचकूला रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है। यह अभूतपूर्व विकास का उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार में विश्वास रखा, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है।

हादसे पर जताया गहरा दुःख, कहा—लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत खिलाड़ी श्री हार्दिक राठी की मृत्यु के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। खेल विभाग और प्रशासन को लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी प्रदेश का गौरव हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार ने पूरे प्रदेश के स्टेडियमों में लगे खेल उपकरणों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट भी मांगी है।

संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति न करें पंजाब सीएम

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा हरियाणा को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी द्वारा एक महीने में पंजाब से नशा खत्म करने का वायदा कर सरकार तो बना ली, लेकिन हालात कैसे हैं वो सबके सामने हैं। नशे की वजह से पंजाब के युवा बर्बाद हो रहे हैं, अपराध भी बढ़ रहा है। बजाय, उस पर कुछ करने के पंजाब सीएम केवल राजनीति कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सिख परंपरा का सम्मान बढ़ाया

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिख परंपरा, गुरुओं की शिक्षाओं और उनके पवित्र स्थलों के सम्मान में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के तीन पवित्र स्वरूपों को सुरक्षित लाने और करतारपुर कॉरिडोर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य उनके प्रयासों से संभव हो सके हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केवल भ्रामक प्रचार कर समाज में विभाजन पैदा करने में लगे रहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अभियान से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे।